भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक
20 मई 2022, जयपुर

– प्रेस वक्तव्य –

राजस्थान की जन विरोधी कांग्रेस सरकार

राजस्थान विविध छटाओं वाला प्रदेश है। यहां के किसान परिश्रमी हैं और यहां के नौजवान बड़ी संख्या में भारत की सेना को ताकत देते हैं। यहां की महिलाएं लोक संस्कृति को जीवन्त बनाती हैं और यहां की अनुसूचित जाति और जनजाति का समाज समरस होकर प्रदेश को विकसित ओर समृद्ध बनाने के लिए काम करता है।

पूरे विश्व में राजस्थान शांति, सद्भाव, समरसता के लिए जाना जाता है। राजस्थान में 70 वर्षों की राजनीति में अधिकांश लगभग 50-55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को शासन करने का अवसर मिला। राजस्थान वर्षों तक बुनियादी विकास को तरसता रहा, एक समय तो राजस्थान की गणना बीमारू राज्य में होती थी। केन्द्र अथवा राज्य में जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहीं यहां के बुनियादी विकास से लेकर सामान्य जन-जन के जीवन स्तर को ऊंचा करने का विभिन्न योजनाओं के जरिये सार्थक एवं सकारात्मक प्रयास हुए।

राजस्थान में कांग्रेस के तीन साल: जनता बेहाल

विगत 2018 से लगभग 42 महीने में यहां कांग्रेस पार्टी का शासन है। राजस्थान के लोग बताते हैं कि इतिहास की अब तक की सबसे नकारा, निकम्मी, अकर्मण्य, भ्रष्ट एवं अराजक सरकार नहीं देखी।

चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रदेश में बुरे हाल हैं। अव्यवस्थाओं के कारण कोटा, अजमेर सहित कई जिलों के अस्पतालों में नवजात बच्चों की असमय मौत हो रही है,

जो बहुत दुखद है और कोटा के अस्पताल के बारे में तो आपको पता ही है वहां तो 100 से अधिक बच्चों की मौत घटिया चिकित्सा व्यवस्थाओं के कारण हुई। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है। राज्य सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना व निःशुल्क दवाई योजना सिर्फ कागजों में बनकर रह गई है। अस्पतालों में दवाईयां नहीं हैं, लोग बाहर से खरीदने को मजबूर हैं और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना राज्य में लागू ही नहीं है।

केन्द्र की श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं जिनमें जन-धन, सौभाग्य, पीएम किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन इत्यादि से देश के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है जो आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है।

वहीं राज्य की कांग्रेस सरकार केन्द्र की योजनाओं को ना तो लागू कर रही है और योजनाओं के नाम बदलकर झूठी वाहवाही लूट रही है, जनता इस बात को भलीभांति जानती है।

किसान विरोधी: कांग्रेस सरकार

राजस्थान कृषि प्रधानता वाला प्रदेश है और प्रदेश की तरक्की में किसानों का बड़ा योगदान है। कांग्रेस पार्टी ने अपने जनघोषणा पत्र से लेकर नेताओं के भाषणों में राज्य के सभी किसानों के संपूर्ण कर्जा माफी का ऐलान करके वोट जरूर बटोरे, लेकिन 10 दिन में कर्जा माफी का वायदा पूरा करना तो दूर बल्कि किसान आत्महत्याओं पर मजबूर हुए और 9 हजार से अधिक उनकी जमीनें नीलाम हो गई।

युवा विरोधी कांग्रेस सरकार

राज्य का बेरोजगार सर्वाधिक त्रस्त है। राज्य में बेरोजगारी दर 32 प्रतिशत से अधिक है जो देश में सर्वाधिक है और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर नौजवानों के साथ छलावा किया गया, भत्ते के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य कर युवाओं को भत्ता लेने से दूर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

विगत तीन वर्षों से लगभग 70 लाख युवाओं ने परीक्षा दी और सरकार ने नौकरी का भरोसा दिया मात्र 1 लाख को, लेकिन नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करने का काम प्रदेश के संगठित नकल एवं पर्चा लीक गिरोह ने किया। रीट से लेकर अनेक परीक्षाओं के पर्चे लीक होने से प्रदेश में अराजकता का माहौल है और इसके लिए कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार सीधे-सीधे जिम्मेदार है। रीट, एसआई, लाईब्रेरियन, पुलिस इत्यादि तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक इस सरकार में हुए हैं।

प्रदेश में कानून व्यवस्था चुनौतीपूर्ण है। सरकार के गठन से लेकर अब तक 7 लाख से अधिक दर्ज मुकदमे इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

कानून व्यवस्था बदहाल, अपराधी बेखौफ, प्रदेश में जंगलराज

कांग्रेस के तीन वर्ष से अधिक शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। बहन-बेटियां प्रदेश में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। औसतन प्रतिदिन 18 दुष्कर्म के मामले व 7 हत्या के मामले सामने आ रहे हैं।

दुष्कर्म व महिला अत्याचार में पहले नंबर पर, अनुसूचित जनजाति वर्ग पर अत्याचारों में दूसरे पर तथा अनुसूचित जाति के प्रति अपराधों में तीसरे नम्बर पर है। कांग्रेस शासन में 300 प्रतिषत अपराध बढ़ गए हैं।

प्रदेश में हर 2 घंटे में एक नाबालिग का अपहरण हो रहा है और एक वर्ष में 4 हजार 124 बालिकाओं का अपहरण हो चुका है। राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना प्रतिदिन हो रही हैं, जिससे प्रदेश जंगलराज की ओर बढ़ रहा है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रदेश में अपराधों में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और सर्वाधिक अपराध उत्पीड़न की घटनाएं महिलाओं, वंचित एवं जनजाति के लोगों पर हुई है।

तुष्टिकरण करने वाली कांग्रेस की गहलोत सरकार

राजस्थान में काग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में वोट बैंक की राजनीति के कारण तुष्टिकरण की सारी हदें लांघ दी।

आज राजस्थान में बहुसंख्यकों पर सुनियोजित हमले किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का पीएफआई के प्रति प्रेम जग जाहिर है। यह तब और प्रमाणित हो गया जब कोरोना के दौरान कोटा में पीएफआई को रैली की इजाजत दी गई, वहीं कानून व्यवस्था के नाम पर हिन्दु नववर्ष और रामनवमी के जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया गया। 17 जिलों में धारा-144 लगाई गई।

करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर और हनुमानगढ़ के नोहर में पिछले 2 महीनों के दौरान सुनियोजित तरीके से अत्याचार हुए और हिंसा हुई।

करौली, जोधपुर सहित राज्य के अनेक शहर इस बात का खुला प्रमाण हैं। साथ ही निर्दोषों को झूठे मुकदमों में फंसाकर तथा दोषियों को खुला छोड़कर प्रतिशोध की राजनीति कांग्रेस कर रही है।

प्रदेश का मेवात क्षेत्र आज अपराधियों का गढ़ बन गया है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, अलवर, झालावाड़ सहित कई जिलों में दलित युवकों को मॉब लिचिंग में पीट-पीटकर मार डाला गया और प्रदेश में सुनियोजित तरीके से दंगे भड़काकर बहुसंख्यक आमजन को भयभीत करने का प्रयास हो रहा है।

अभी हाल ही में राजगढ़ (अलवर) में 300 वर्ष पुराने शिव मंदिर को ध्वस्त किया जाना इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

यह हास्यास्पद है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं दंगों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जनता सब देख रही है, जान चुकी है।

जनविरोधी कांग्रेस सरकार

आज राजस्थान के हालात बदतर हैं, प्रदेश में आर्थिक आपातकाल जैसे हालात हैं, लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पानी-बिजली के लिए हाहाकार मचा रहे हैं। अस्पताल बीमार हो रहे हैं और स्कूल तथा शिक्षा व्यवस्था लाचार है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।

ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में यह संकल्प लिया जाता है कि 2023 में गरीब विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, जनविरोधी, हिन्दू विरोधी कांग्रेस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से प्रचण्ड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाएंगे तथा राज्य के हितों की रक्षा तथा लोक कल्याण का काम करेंगे और राजस्थान को फिर से शांतिप्रिय व जनसुरक्षा वाला प्रदेश बनाते हुए विकास के नए पथ पर लेकर जाएंगे।